विपक्ष के नैरेटिव पर पलटवार करेगी भाजपा

वोटबैंक के सिकुड़ने की आहट से भाजपा व संघ के रणनीतिकार बेचैन

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. पिछले कुछ समय से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों द्वारा मुद्दों के आधार पर केन्द्र सरकार को आक्रामक अंदाज में घेरने की प्रक्रिया आरंभ हुई है , उसको लेकर भाजपा व संघ के अंदर बेचैनी बढ़ गई है.

सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से विपक्षी खेमों द्वारा भाजपा से आगे निकलने के प्रयास के तहत शासन के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है उसके कारण भाजपाई रणनीतिकारों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. ऐसे में जहां एक तरफ भाजपा अब आक्रामकता की जगह समावेशी और रक्षात्मक रुख अपना रही है



वहीं सरकार अब लोक-लुभावन आर्थिक नीतियों, युवाओं के लिए रोजगार केंद्रित योजनाओं और मध्यम वर्ग को सीधे राहत देने वाले एजेंडे पर फोकस करते हुए विपक्षी हमलों की धार को कुंद करने में जुटी है. राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि यह बदलती राजनीतिक शैली इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष केवल संख्या बल के सहारे नहीं, बल्कि रणनीतिक धार के साथ पुनर्जीवित हुआ है. लोकसभा चुनावों के बाद बदले हुए संख्या बल और संसद से सड़क तक बढ़े राजनीतिक तापमान ने एक दशक पुराने परंपरागत राजनीति को बदल दिया है. कल तक जिस राहुल गांधी और कांग्रेस को भाजपा आसानी से रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर देती थी, आज वही विपक्ष सरकार को सीधे मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रहा है. इसे केवल एक संयोग या भाजपाई रणनीतिकारों की रणनीतिक चूक नहीं कहा जा सकता है बल्कि इसे विपक्ष द्वारा नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने की सफलतम कोशिश के रूप में देखा जा सकता है.

संघ का गंभीर वैचारिक मंथन जारी

जानकार बता रहे हैं कि बदलते राजनीतिक माहौल में भाजपा अपने खिसकते या सिकुड़ते वोटबैंक की संभावित आहट को लेकर ज्यादा चिंतित है. संघ के भीतर भी इस विषय पर गंभीर वैचारिक मंथन जारी है. संघ का मानना है कि सत्ता के अतिआत्मविश्वास के कारण जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच अब दूरी पैदा होती दिख रही है. ऐसे में संघ द्वारा आंतरिक स्तर पर समन्वय बैठकें तेज कर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास आरंभ किया गया है. संघ द्वारा सीधे राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से ड्राइंग रूम मीटिंग्स और मोहल्ला बैठकों का एक व्यापक वैचारिक संवाद अभियान आरंभ किया गया है. जबकि भाजपा अब युवा पीढ़ी यानी जेन जी की बदलती आकांक्षाओं को समझने के लिए विशेष सांगठनिक सत्र आयोजित कर रही है और वैचारिक रूप से उन्हें जोड़ने की मुहिम में लगी है.

भस्मासुरों पर ही नहीं रहा पाक का कंट्रोल

यूएन में भारत ने उतारा पाकिस्तान का नकाब

न्यूयॉर्क, 8 अक्टूबर(एजेंसी). दुनिया के सामने इस्लामाबाद के दोहरे रवैये को उजागर करते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो 'फ्रेंकस्टीन मॉन्स्टर' (भस्मासुर) बनाया था उस पर उसका नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका है. उसका पाला हुआ भस्मासुर अब उन्हीं लोगों पर हिंसक हमले कर रहा है जिन्होंने इसे बनाया था.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी राघू पुरी ने कहा, 'पाकिस्तान ने खुद को आतंकवाद से लड़ने वाले देश और पीड़ित के तौर पर पेश किया है लेकिन वह इस बात को छिपाता रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने जिन 'फ्रेंकस्टीन' (खतरनाक राक्षसों) को बनाया और जिन पर से अपना कंट्रोल खो दिया वे अब पड़ोसी देशों में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान में भी वही सब



कर रहे हैं. यूएन जनरल असेंबली की छठी कमिटी (जो कानूनी मामलों को देखती है) की कार्यवाही के दौरान पुरी पाकिस्तान के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उस्मान जादून द्वारा नई दिल्ली के खिलाफ बिना किसी उकसावे के की गई तीखी आलोचना के जवाब में भारत का पक्ष रख रहे थे. पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे के अंदरूनी विरोधाभासों को उजागर करते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पिछले महीने लाहौर में कहा, दुर्भाग्य से 13 करोड़ की आबादी वाले पंजाब प्रांत को खतरा मेरे पड़ोसी देशों से कम और मेरे पड़ोसी प्रांतों से ज्यादा है.

पाक ने ही उजागर किया काला सच

उन्होंने कहा, 'हाल ही में पाकिस्तान की एक प्रांतीय मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा किया था. मैं अपने साथियों को 2018 में उनके पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की याद दिलाना चाहूंगा जिसमें इस काले सच को उजागर किया गया था.' पुरी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'आप एक ही समय में दो विरोधी पक्षों का साथ नहीं दे सकते. असलियत ऐसी नहीं होती.

जंतर-मंतर पर हुई हिंसा की जांच शुरू

नई दिल्ली. 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के मार्च के दौरान हिंसा हो गई थी. इस मामले में कई प्रदर्शनकारियों के साथ ही पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी. अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी. क्राइम ब्रांच 20 जुलाई को हुई हिंसा की वजहों की पड़ताल करेगी. इसमें जांच की जाएगी कि ये हिंसा कहीं पहले से प्लान तो नहीं की गई थी या इस हिंसा के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी. क्राइम ब्रांच ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. क्राइम ब्रांच इन सभी घटनाओं को आपस में जोड़कर मामले की तह तक जाने का प्रयास करेगी.

मोदी-ट्रंप के रिश्तों ने बढ़ाई भारत-अमेरिका की ताकत

▶ व्हाइट हाउस ने कहा मोदी और ट्रंप का मजबूत रिश्ता

वाशिंगटन, 8 अक्टूबर (एजेंसी). भारत और अमेरिका के रिश्तों में व्यापार और कुछ नीतिगत मुद्दों को लेकर व्हाइट हाउस ने भारत को अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक बताया है.

साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों को द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने में अहम बताया. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि



भारत अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में है और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंधों से यह साझेदारी और मजबूत हुई है. व्हाइट हाउस की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं. 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए.

17,500 फीट की ऊंचाई पर सेना के ड्रोन

भारतीय सेना चीन सीमा पर निगरानी करेगी और मजबूत

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. भारतीय सेना ने 225 फर्स्ट-पर्सन व्यू ड्रोन का एक ऑर्डर दिया है. यह फैसला कड़े मूल्यांकन और कड़े मैदानी परीक्षणों के बाद लिया गया है, जिनमें 17500 फीट तक की अत्यधिक ऊंचाई पर इनका सफल परीक्षण किया गया था.

वैसे तो यह ऑर्डर संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस कठिन परिस्थिति और ऊंचाई पर इन ड्रोनों का परीक्षण और चयन किया गया है, वह इसे बेहद खास बनाता है. इन ड्रोनों को उनकी सहनशक्ति, सटीकता, रफ्तार और



उच्च पहाड़ी इलाकों में काम करने की क्षमता के आधार पर परखा गया है.चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक 12000 से लेकर 18000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात हैं. अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से न सिर्फ इंसानी क्षमता प्रभावित होती है.

ड्रोन उड़ाना भी बड़ी चुनौती

दूसरी ओर, यह सब इतना आसान भी नहीं है. समुद्र तल से 15000 फीट की ऊंचाई पर हवा का घनत्व लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है. इसकी वजह से ड्रोन के पंखों को पकड़ने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिलती, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट काफी कम हो जाता है. इसके अलावा भी कई बड़ी तकनीकी मुश्किलें सामने हैं. हवा कम होने के कारण मोटरों को ठंडक नहीं मिलती, जिससे वे भारी लोड के कारण जल्दी गर्म होकर जल सकती हैं. इसके अलावा कड़ाके की ठंड में लिथियम-आधारित बैटरियां धीमी हो जाती हैं.

बिहार के मजदूरों को झांसा देकर रतलाम में बनाया बंधक

▶ वीडियो वायरल होने पर मामला आया सामने

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ, 8 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रोजगार दिलाने का झांसा देकर बिहार के गोपालगंज जिले के करीब एक दर्जन मजदूरों को मध्य प्रदेश के रतलाम में बंधक बनाकर काम कराने का गंभीर मामला सामने आया है.

एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी सुरक्षा की गुहार



लगाई है. मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरन सरिया बांधने समेत अन्य भारी काम कराया जा रहा है, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा. मजदूरों ने पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी और स्थानीय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है.

देश आर्थिक संकट की ओर सरकार जश्न में व्यस्त

▶ रेपो रेट बढ़ने पर केंद्र पर कांग्रेस का तीखा हमला

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. रेपो दर में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है.

कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री अपने 25 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने में व्यस्त हैं. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर सरकार पर तंज कसते हुए 1961 में आई देव आनंद अभिनीत



फिल्म 'हम दोनों' के गीत की पंक्तियों का उल्लेख करके लिखा, बरबादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया.रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के बाद मौजूदा ऋणों की किस्त और नए कर्ज की लागत बढ़ सकती है. यह बढ़ोतरी त्यौहारी मौसम से पहले की गई है. विपक्षी दल की यह टिप्पणी आरबीआई द्वारा बुधवार को बेंचमार्क रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत किए जाने के एक दिन बाद आई.

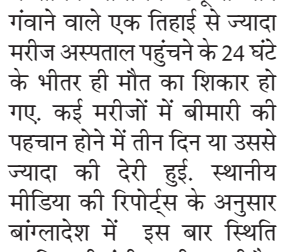
झारखंड में डीजीपी नियुक्ति पर घिरी सरकार

सुप्रीम कोर्ट बोला- नियम हमारे पुराने फैसले के खिलाफ

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के नियमों पर कड़ी आपत्ति जताई है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पहली नजर में ये नियम सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ नजर आते हैं. अदालत ने डीजीपी बनाई गई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा से भी जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. साथ ही राज्य से कहा है कि यदि वह नियम



में बदलाव नहीं करना चाहता है, तो उसे अदालत के समक्ष इसका बचाव करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों को रद्द करने की स्थिति में तदाशा मिश्रा प्रभावित हो सकती हैं. इसलिए अदालत उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दे रही है. सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर किसी दूसरे राज्य ने भी ऐसे नियम बनाए हैं तो सत्ता में किसी भी दल की सरकार हो, ऐसे नियमों को हटना चाहिए. दरअसल, राज्य के नियमों में छह महीने से कम सेवा अवधि वाले अधिकारी को भी डीजीपी बनाने की अनुमति दी गई है.

केंद्र ने नियमों को दी चुनौती

केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की ओर से 8 जनवरी 2025 को जारी 'झारखंड डीजीपी चयन और नियुक्ति विनियमन, 2025' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केंद्र का कहना है कि ये नियम पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले के अनुरूप नहीं हैं. झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार इन नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र पहले भी झारखंड सरकार को बता चुका है कि ये नियम प्रकाश सिंह मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ हैं और इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता.

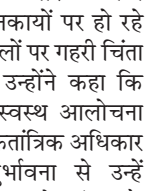
राहुल से सवाल पर युवक की पिटाई, मचा बवाल

▶ भाजपा ने कांग्रेस पर साधा सीधा निशाना

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट का वीडियो सामने आया है.

यह वही रेस्टोरेंट है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया था. खुद को श्रीनगर का रहने वाला फहीम नजीर बताने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसने राहुल गांधी को गाली नहीं दी थी,



लेकिन इसके बावजूद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई. फहीम ने कहा कि वह देश के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश हो रही है. उसने ईवीएम को लेकर भी दावा किया और कहा कि ईवीएम पहली बार 1998 में राजीव गांधी के समय लाई गई थी. फहीम ने कहा कि इस संबंध में फुटेज भी मौजूद है और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए. उसने अपनी बात को अभिव्यक्ति की आजादी बताया.

यूएस में 30वें व्यक्ति को मौत की सजा

वाशिंगटन. अमेरिका के टेक्सस में बुधवार को एक कैदी को मौत की सजा दी गई. उसने स्टोर क्लर्क की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वह इस साल अमेरिका में मौत की सजा पाने वाला 30वां व्यक्ति था. टेनेसी में क्रिस्टा पाइक को जानलेवा इंजेक्शन देने की नाकाम कोशिश के बाद यह पहली मौत की सजा थी. 46 वर्षीय जमाल हावर्ड को हंट्सविले की स्टेट जेल में जहरीले इंजेक्शन की डोज दिए जाने के बाद बुधवार रात 8:03 बजे (स्थानीय समय) मृत घोषित कर दिया गया. उसने वर्ष 2000 में एक स्टोर में हुई लूट के दौरान 42 वर्षीय विकी स्वार्टआउट की हत्या कर दी थी. जेल वार्डन ने जब आखिरी इच्छा पूछी, तो उसने पीड़िता के परिवार के सदस्यों से माफी मांगी, जो कुछ दूरी पर खिड़की से यह सब देख रहे थे.

एक नजर में

पहली बार हिंदू नेता को शीर्ष संगठनात्मक जिम्मेदारी

तिरुवनंतपुरम. केरल की राजनीति में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संगठनात्मक स्तर पर एक अहम बदलाव किया है. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सहयोगी पार्टी आईयूएमएल ने पहली बार किसी गैर-मुस्लिम नेता को राज्य संगठन के शीर्ष पदों में से एक की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी ने 61 वर्षीय सी श्याम को राज्य का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. बुधवार को संगठन में बदलाव की घोषणा की गई. इससे पहले वह सीपीआई की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में राज्य स्तर पर सक्रिय रहे हैं.

नेपाल के बजुरा में 4.1 तीव्रता के झटकों से दहशत

काठमांडू. नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार स्थानीय समयानुसार रात 9:37 बजे 4.1 तीव्रता का कंपन दर्ज किया गया. इसका केंद्र सुदूरपश्चिम प्रांत के बजुरा जिले की बुधीगंगा नगरपालिका-10 में जमीन के भीतर स्थित था. राजधानी काठमांडू से यह स्थान करीब 750 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है.

मुंबई के लेबर कैंप में 7 गैस सिलेंडर फटने से दहशत

मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मुलुंड ईस्ट स्थित टाटा कॉलोनी के लेबर कैंप में गुरुवार को भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कैंप में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर कैंप से बाहर निकल आए. आग के दौरान एक के बाद एक 7 गैस सिलेंडर फटने की सूचना है. सिलेंडर धमाकों का वीडियो भी सामने आया है. यह लेबर कैंप धारावी से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट परिसर में स्थित बताया जा रहा है.

हस्तियों के ट्वीट



टेस्ला के सीईओ और उद्योगपति एलन मस्क ने एक्स पर परिपक्वता को लेकर एक विचार साझा किया। उन्होंने लिखा, 'परिपक्वता का मतलब हर चीज को ठीक करना जानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि किसे सुधारना जरूरी है, किसे स्वीकार करना चाहिए और किसे पीछे छोड़ देना ही बेहतर है. मस्क का यह संदेश जीवन में प्राथमिकताएं तय करने और परिस्थितियों को समझने की अहमियत पर जोर देता है. उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं.



सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'राज समानी' ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कई बार हम सच्चाई से इसलिए दूर भागते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि सच जानने के बाद हमें कुछ करना पड़ेगा. हम रिपोर्ट नहीं देखते, सवाल नहीं पूछते, आंकड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को अनजान बनाए रखते हैं. लेकिन याद रखिए, अनजान रहना हमेशा सुकून नहीं देता, कभी-कभी यह सिर्फ जिम्मेदारी से बचने का आसान रास्ता होता है.सच्ची परिपक्वता इस बात में है कि हम असहज करने वाली जानकारी का सामना करने का साहस रखें.

बांग्लादेश में डेंगू से 281 मौत, 90 हजार संक्रमित

▶ 90 हजार से ज्यादा लोग हुए संक्रमित

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. बांग्लादेश में इस समय एक साथ दो संक्रामक बीमारियां चिंता बढ़ा रही हैं. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक बांग्लादेश में डेंग के 90 हजार से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचना पड़ा है और 281 लोगों की मौत हो चुकी है. अक्तूबर में ये चिंता और भी बढ़ती देखी जा रही है. डेंगू की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बढ़ते मामले नहीं हैं, बल्कि बीमारी की



देर से पहचान भी है. एक समीक्षा में सामने आया कि डेंगू से जान गंवाने वाले एक तिहाई से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर ही मौत का शिकार हो गए. कई मरीजों में बीमारी की पहचान होने में तीन दिन या उससे ज्यादा की देरी हुई. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में इस बार स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है.

आज का इतिहास

1776 - अमेरिकी संसद ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनी से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया.

1876 - पहली बार टेलीफोन पर आउटडोर वायर के माध्यम से दो-तरफा बातचीत हुई. यह बातचीत बोस्टन में रह रहे बेल और कैम्ब्रिज में रह रहे वॉटसन के बीच हुई.

1920- अलीगढ़ का एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदला.

1945- प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खां का जन्म.

आलोचना का अधिकार, बदनाम करने का नहीं

42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में लिखा पत्र

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. देश में सांविधानिक संस्थाओं की साख और उनकी स्वायत्तता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. इसी बीच 42 पूर्व जजों और सेवानिवृत्त सांविधानिक अधिकारियों ने भारत के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा.

जजों ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन आज के दौर में साधे रखी गई चुप्पी निष्पक्षता नहीं हो सकती. उनका मानना है कि जब देश की बुनियादी संस्थाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा हो, तब सामने आकर सच बोलना बेहद जरूरी हो जाता है. इस खुले पत्र में 42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य सांविधानिक निकायों पर हो रहे सुनियोजित हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि संस्थाओं की स्वस्थ आलोचना करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दुर्भावना से उन्हें बदनाम करना लोकतंत्र के खिलाफ है. मंचों से सांविधानिक संस्थाओं को खुलेआम चोर, कठपुतली और समझौतावादी कहना बेहद खतरनाक है. बिना किसी कानूनी सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किया जाता.

एसआईआर को लेकर है विवाद

पूर्व जजों ने समझाया कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से अपनी शक्ति लेता है. संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर मतदाता सूची को कार्यपालिका की पहुंच से दूर एक स्वतंत्र आयोग को सौंपा था. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, जो पहले आम चुनाव के समय से ही नियमित रूप से होती आई है. इसका उद्देश्य मृत लोगों के नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियां खत्म करना और छूटे हुए पात्र नागरिकों को जोड़ना है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह वैध और निष्पक्ष माना है, फिर भी तथ्यों को दरकिनार कर भ्रम फैलाया जा रहा है.

सावधानी | डब्ल्यूएमओ ने किया अलर्ट, नक्शे में लाल रंग में आधी से ज्यादा पृथ्वी

ठंड में भी पसीना छुड़वाएगा सुपर अल नीनो

वाशिंगटन, 8 अक्टूबर (एजेंसी). दुनिया भर के मौसम विशेषज्ञ अल नीनो के बारे में चेतावनी दे रहे है और इसके ऐसी स्थिति में पहुंचने का दावा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई. संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस साल के मौसम का घटनाक्रम साल 1950 के बाद से देखे गए सबसे मजबूत घटनाक्रमों में से एक हो सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में भारी मात्रा में जमा हुई गर्मी के बाहर निकलने के कारण आने वाले महीनों में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा असामान्य



रूप से गर्म रहेगा. मौसम वैज्ञानिक रयान माउ ने पूरी पृथ्वी का एक जलवायु नक्शा पोस्ट किया और कहा कि पृथ्वी लगभग पूरी तरह से लाल रंग में दिख रही है. वैज्ञानिक ने एक्स पर कहा, 'अल नीनो सर्दियों में भी अपनी पूरी ताकत के साथ बना रहेगा और अमेरिका को छोड़कर हर जगह पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा.' वैज्ञानिक ने डब्ल्यूएमओ के इस अनुमान से सहमति जताई है कि अल नीनो फरवरी 2027 तक बना रहेगा. एक और वैज्ञानिक जेक हॉसफादर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'इस साल का अल नीनो ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई है.

अल नीनो बढ़ता है गर्मी

अल नीनो प्राकृतिक रूप से होने वाले अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन चक्र का गर्म चरण है, यह एक ऐसा जलवायु पैटर्न है जो दुनियाभर के मौसम को प्रभावित करता है. अल नीनो के कारण आमतौर पर वैश्विक तापमान बढ़ता है और बड़े क्षेत्रों में बारिश का पैटर्न बिगड़ जाता है यानी कुछ इलाकों में सूखा पड़ता है तो कुछ में भारी बारिश होती है और यह आमतौर पर हर दो से सात साल में होता है. शिकागो यूनिवर्सिटी की क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के रिसर्चर्स ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि इस साल के सुपर अल नीनो के कारण जून से फरवरी 2027 के बीच दुनिया भर में 4 लाख 51 हजार से ज्यादा मौतें हो सकती हैं.

सुको ने पंजाब के 50 वार्डों में दोबारा मतदान के दिए आदेश

चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत पर फैसला

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य के 50 नगर निकाय वार्डों में हुए चुनाव को रद्द कर दिया है. अदालत ने इन वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है.

मामला चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट, धमकी और जबरन नामांकन पत्र छीनने से जुड़ा है. अदालत ने दोबारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला जिले के 28 और मोगा जिले के 22 वार्डों के चुनाव रद्द किए हैं. अदालत ने यह फैसला पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया. आयोग ने पाया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़े स्तर पर रुकावट डाली गई थी. आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीन लिए गए, फाड़ दिए गए या नष्ट कर दिए गए. कुछ उम्मीदवारों के साथ मारपीट की गई, उन्हें रोका गया या धमकाया गया.